प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

13.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 9:20बजे

''आज के मुख्य समाचार''

- राज्य मंत्रिमंडल ने टोल टैक्स बैरियर नीति और आबकारी नीति को दी मंजूरी–दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता राशि में वृद्धि
- केंद्र ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए हिमाचल सहित पांच राज्यों को 3 हजार 3 सौ 24 करोड़ रूपये से अधिक की राशि की स्वीकृत
- प्रदेश सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक–राजस्व घाटा अनुदान बंद होने पर प्रदेश के वितीय हालात पर होगी चर्चा

और

- टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत चंबा जिले में टीवी उपचार की सफलता दर रही संतोषजनक

अब समाचार विस्तार से.....

मंत्रिमंडल

राज्य मंत्रिमंडल ने टोल कर बाधा नीति 2026–27 और उत्पाद शुल्क नीति 2026–27 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में हुई निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने बताया कि बैठक में प्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र में राज्यपाल द्वारा दिए जाने वाले अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत विधवाओं की बेटियों को राज्य के भीतर और बाहर सरकारी संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता राशि में भी वृद्धि की है।

पंचायती राज – अनुदान

केन्द्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए तीन हजार 3 सौ 24 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। यह निधि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में जारी हुई है जो हिमाचल प्रदेश सहित पांच राज्यों बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को दी जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि अप्रतिबंधित अनुदानों का उपयोग स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा है कि इस राशि का प्रयोग स्वच्छता की बुनियादी सेवाओं, खुले में शौच मुक्त यानि ओडीएफ स्थिति के रखरखाव, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी सुविधाओं के लिए भी किया जा सकता है।

सर्वदलीय बैठक

प्रदेश सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान यानी आर.डी.जी. बंद होने से प्रदेश के वितीय हालात पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक शिमला स्थित राज्य सचिवालय में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के अलावा भाजपा अध्यक्ष व अन्य दलों के नेताओं को बुलाया गया है। वित विभाग इस बैठक में प्रदेश की वितीय स्थिति पर प्रस्तुति देगा।

विश्व रेडियो दिवस

आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है– "रेडियो और एआई– एक उपकरण है, आवाज नहीं।" यह थीम प्रसारण व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है। यह दर्शाती है कि एआई के जरिए सामग्री निर्माण, अभिलेखीकरण, अनुवाद, श्रोताओं की भागीदारी और पहुंच को बेहतर बनाकर रेडियो को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाया जा सकता है। साथ ही, थीम के जरिए यह भी संदेश दिया गया है कि तकनीक मात्र सहायक माध्यम है, वह मानवीय आवाज का स्थान नहीं ले सकती। संपादकीय विवेक और विश्वसनीयता ही रेडियो की असली पहचान हैं।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य के सभी विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और उसे अधिक मजबूत बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि विद्यालय बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होने चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कांगड़ा जिला के देहरा क्षेत्र की चनौर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में मिड–डे मील वर्कर सलोचना देवी की हत्या की घटना पर गहरा दुःख व्यक्त जताते हुए

इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून के अनुसार सख्त व आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

टीबी मुक्त अभियान

देश को टी बी मुक्त बनाने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में आकांक्षी जिला चंबा अहम भूमिका निभा रहा है। चम्बा जिला में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत वर्ष–2025 में कुल 23 हजार 9 सौ 15 लक्ष्य के मुकाबले 26 हजार 8 सौ 95 मामलों की जांच की गई। जिले में टीबी उपचार की सफलता दर भी संतोषजनक रही है।

डिस्पैच–

जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के कठिन परिश्रम का ही परिणाम है कि टी बी मुक्त भारत अभियान की सफलता में जिला चम्बा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान हेतु जिले में व्यापक स्तर पर संभावित टीबी जांचें की गई हैं। जिले में कुल 1202 टीबी रोगियों में से 1171 रोगियों की एचआईवी स्थिति ज्ञात की जा चुकी है। वहीं निक्षय मित्र पहल के माध्यम से टीबी रोगियों को पोषण सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। जिले में कुल 646 रोगी उपचाराधीन हैं, जिनमें से 514 रोगियों को समुदाय एवं निक्षय मित्रों द्वारा पोषण सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 3 अल्ट्रा पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स–रे मशीनें आवंटित की गई हैं तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

प्रदर्शन

बिजली संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने कल प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। विधेयक के विरोध में बोर्ड के कर्मचारी टूल डाउन और पैन डाउन स्ट्राईक पर रहे। विद्युत बोर्ड संयुक्त समन्वय समिति के सह–संयोजक हीरा लाल वर्मा ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। शिमला स्थित विद्युत बोर्ड मुख्यालय के बाहर भी कर्मचारियों ने बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया और बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन योजना बहाल करने की मांग की।

और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से.....

आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है।

अमर उजाला की सुर्खी है–**शराब महंगी होगी, बाहरी वाहनों के लिए बढ़ेगा प्रवेश शुल्क, लॉटरी करेंगे शुरू।** पंजाब केसरी के शब्द हैं–**एक हजार 66 पद भरेंगे, बंद नहीं होगी ओ.पी.एस., कर्मचारियों को मिलता रहेगा डीए व एरियर।** दिव्य हिमाचल का शीर्षक है–**सुक्खू सरकार लाई एक हजार 66 नई नौकरियां।** दैनिक जागरण का कहना है–**हिमाचल में बंद नहीं होगी ओपीएस व सब्सिडी, लॉटरी से कमाई करेगी सरकार।** हिमाचल दस्तक लिखता है–**जारी रहेगी पात्रों को सब्सिडी और कर्मचारियों को ओपीएस।** दैनिक भास्कर की सुर्खी है–**आर्थिक तंगी के बावजूद नौकरियां का पिटारा खुला, नहीं बंद होगी ओपीएस।** दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं–**सुक्खू सरकार का बड़ा रोजगार फैसला, हजार से ज्यादा पद भरने को मंजूरी।** आपका फैसला के मुताबिक–**टोल टैक्स बैरियर नीति तथा आबकारी नीति को मंजूरी।**

''अंत में मुख्य समाचार'' एक बार फिर

- राज्य मंत्रिमंडल ने टोल टैक्स बैरियर नीति और आबकारी नीति को दी मंजूरी–दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता राशि में वृद्धि
- केंद्र ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए हिमाचल सहित पांच राज्यों को 3 हजार 3 सौ 24 करोड़ रूपये से अधिक की राशि की स्वीकृत
- प्रदेश सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक–राजस्व घाटा अनुदान बंद होने पर प्रदेश के वितीय हालात पर होगी चर्चा

  और
- टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत चंबा जिले में टीवी उपचार की सफलता दर रही संतोषजनक

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे नमस्कार।